



NEERAJ®

परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति

(India's Foreign Policy in a Globalising World)

B.P.S.E.-142

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Dr. Kusam Kumari*



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति (India's Foreign Policy in a Globalising World)

Question Paper—June-2024 (Solved).....	1
Question Paper—December-2023 (Solved).....	1-3
Question Paper—June-2023 (Solved).....	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved).....	1
Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved).....	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

प्रस्तावना

(Introduction)

1. भारत की विदेश नीति का विकास	1
(Evolution of India's Foreign Policy)	
2. भारत की विदेश नीति के निर्धारक	13
(Determinants of India's Foreign Policy)	
3. भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं उद्देश्य.....	22
(Principles and Objectives of India's Foreign Policy)	
4. भारत विदेश नीति-निर्माण : संस्थाएं व तंत्र.....	34
(Making of India's Foreign Policy: Institution and Mechanisms)	

प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की नीति

(India's Policy Towards Major Powers)

5. यूएसए (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) के प्रति भारत की नीति.....	44
(India's Policy Towards USA)	
6. रूस के प्रति भारत की नीति.....	56
(India's Policy Towards Russia)	
7. चीन के प्रति भारत की नीति संरचना.....	69
(India's Policy Towards China)	

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
भारत की दक्षिण एशिया नीति (India's South Asia Policy)		
8.	पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति..... (India's Policy Towards Pakistan)	78
9.	अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति..... (India's Policy Towards Neighbours)	88
भारत और आस-पास के क्षेत्र (India and Its Regions)		
10.	भारत की एकट ईस्ट नीति..... (India's Act East Policy)	104
11.	भारत तथा मध्य एशिया और पश्चिम एशिया..... (India and Cultural Asia and West Asia)	113
12.	अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की नीति..... (India's Policy Towards Africa and Latin America)	124
वैश्वीकरण दुनिया में भारत की चिंताएँ (India's Concerns in the Globalising World)		
13.	सुरक्षा चिंताएँ..... (Security Concerns)	134
14.	पर्यावरण संबंधी चिंताएँ..... (Environmental Concerns)	143
15.	आर्थिक संबंध..... (Econmic Concerns)	152



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति
(India's Foreign Policy in a Globalising World)

B.P.S.E.-142

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्रश्न 1. भारत की विदेश नीति के विकास और स्वतंत्रता आन्दोलन में इसके मूल (roots) पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति' तथा पृष्ठ-2, 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विदेश नीति मूल्य'

प्रश्न 2. भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-17, प्रश्न 2

प्रश्न 3. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की उभरती प्रकृति पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-5, पृष्ठ-46, प्रश्न 1

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए-
(क) भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में राष्ट्रीय हित

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-23, 'राष्ट्रीय हितों का संरक्षण एवं संवर्धन' तथा पृष्ठ-28, प्रश्न 3, 'विदेश नीति में राष्ट्रीय हित'

(ख) भारत का रूस के साथ संबंध

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-6, पृष्ठ-58, 'भारत-रूस संबंधों की संभावनाएं' तथा प्रश्न 1

(ग) भारत-चीन संबंध

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-72, प्रश्न 3

(घ) 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-8, पृष्ठ-78, 'परिचय' तथा पृष्ठ-79, '1965 का भारत-पाक युद्ध'

प्रश्न 5. अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की सुरक्षा की समकालीन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-136, प्रश्न 2 तथा पृष्ठ-134, 'सुरक्षा का निर्धारण'

प्रश्न 6. भारत की विदेश नीति में श्रीलंका के सामरिक महत्त्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-91, 'श्रीलंका : एक भू-रणनीतिक अवलोकन'

प्रश्न 7. भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' के महत्त्व की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-10, पृष्ठ-105, 'एक्ट ईस्ट नीति' तथा पृष्ठ-109, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'

प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-
(क) मध्य एशिया का भू-रणनीतिक महत्त्व

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-11, पृष्ठ-116, प्रश्न 1

(ख) भारत-अफ्रीका संबंध का महत्त्व

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-126, प्रश्न 1

(ग) 21वीं शताब्दी में भारत की मानव सुरक्षा की चुनौतियाँ

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-137, प्रश्न 3

(घ) भूमंडलीकरण के युग में भारत की पर्यावरणीय नीतियाँ

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-14, पृष्ठ-143, 'वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और पहल' तथा पृष्ठ-146, प्रश्न 2

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति
(India's Foreign Policy in a Globalising World)

B.P.S.E.-142

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्रश्न 1. 1947 से विभिन्न चरणों में कार्य कर रही भारत की विदेश नीति का अवलोकन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 1 तथा प्रश्न 2

प्रश्न 2. भारत की विदेश नीति के निर्माण में विभिन्न सरकारी संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-37, प्रश्न 3

प्रश्न 3. शीतयुद्धोत्तर युग में प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-5, पृष्ठ-47, प्रश्न 2

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) भारत-रूसी सामरिक संबंध

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-6, पृष्ठ-61, प्रश्न 3

(ख) 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-8, पृष्ठ-79, '1971 का युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति'

(ग) मध्य एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंध

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-11, पृष्ठ-117, प्रश्न 2

(घ) भारत-लैटिन अमेरिका संबंध

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-125, 'भारत-लैटिन अमेरिका संबंध'

प्रश्न 5. भारत की विदेश नीति के बदलते स्वरूप का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-मई 2014 में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से भारतीय विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव आया है, जो हाल की बौद्धिक और राजनीतिक बहसों में परिलक्षित होता है। थोड़े से समय में प्रशासन एक विशिष्ट विरासत बनाने में सफल रहा है, जो भारत को एक प्रमुख वैश्विक अभिनेता के रूप में स्थापित करने का उसका लक्ष्य बनाता है।

भारतीय विदेश नीति के विकास के चरण

प्रथम चरण (1946-62) : आशावादी गुटनिरपेक्षता का युग-शीत युद्ध और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में जैसे ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया और अपनी अखंडता को मजबूत किया, उसने अपने विकल्प सीमित होने और अपनी संप्रभुता कम होने से बचने की कोशिश की। इसका द्वितीयक उद्देश्य, उपनिवेशमुक्त देशों में से पहले के रूप में, एक अधिक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की खोज में एशिया और अफ्रीका का मार्गदर्शन करना था। यह तीसरी दुनिया की एकता का चरम था, और इसके अतिरिक्त इसने कोरिया और वियतनाम से लेकर हंगरी और स्वेज तक सक्रिय भारतीय कूटनीति देखी। कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भारत की स्थिति सुरक्षित एवं स्थिर दिखाई दी, लेकिन 1962 में चीन के साथ टकराव ने इस समय सीमा को समाप्त कर दिया और इसका भारत की स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

दूसरा चरण (1962-71) : यथार्थवाद और पुनर्प्राप्ति का दशक-कम संसाधन होने के बावजूद, भारत ने व्यावहारिक तरीके से सुरक्षा और राजनीतिक चिंताओं का जवाब दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़ गया और 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अब काफी हद तक भुला दिया गया है। इस नाजुक समय में कश्मीर पर बाहरी दबाव बढ़ गया। हालांकि वैश्विक वातावरण विभाजित रहा, कुछ छिटपुट यूएस-यूएसएसआर सहयोग था। दक्षिण एशिया के भौगोलिक अभिसरण के कारण भारत की कूटनीति को महाशक्तियों को एक साथ शामिल करना पड़ा, जैसा कि 1965 में ताशकंद में हुआ था। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसा समय था जब राजनीतिक अशांति और आर्थिक कठिनाई जैसी घरेलू समस्याएं बेहद तीव्र थीं।

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति (India's Foreign Policy in a Globalising World)

प्रस्तावना (Introduction)

भारत की विदेश नीति का विकास (Evolution of India's Foreign Policy)



परिचय

किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास के गहरा संबंध रखती है। भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखती है। ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज उन अनेक तथ्यों को समेटे हुए है, जो कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे थे। भारत की विदेश नीति के निर्माण का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1932 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल प्रकृति और कामकाज को देखते हुए दुनिया के साथ अपने व्यवहार में एक पृथकतावादी नीतिगत प्राथमिकता नहीं रख सकता है। वर्तमान में सभी देशों की परस्पर संबंधों में वैश्विक मामलों में सक्रिय भागीदारी है। भारत के मामले में कई ऐसे कारक हैं, जिन्होंने देश को एक निश्चित और व्यापक विदेश नीति विकसित करने के लिए तैयार किया।

अध्याय का विहंगावलोकन

भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति

स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की जड़ें उन प्रस्तावों व नीतियों में ढूँढ़ी जा सकती हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के पश्चात (1885-1947) महत्वपूर्ण विदेश नीति के विषयों पर अपनाई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक सरकार ने भारत को वैश्विक राजनीति के भंवर में धकेलने से कोई संकोच नहीं किया। ब्रिटेन द्वारा अपनी स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनिवार्य रूप से एक पार्टी बना दिया गया

था। पराधीन भारत की विदेश नीति का निर्माण 1885 में स्थापित इंडिया हाऊस लंदन में होता था। अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन फिर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति' का दर्जा प्राप्त कर चुका था तथा कई विषयों पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं के सकारात्मक परिणाम निकलने के साथ स्वतंत्र भारत की नीतियों हेतु ठोस आधार भी तैयार हो गया था। इसी आधार पर पराधीन भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी प्राप्त होने लगी। इसी के परिणामस्वरूप ही भारत से फ्रांसिस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के समय संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने की दिशा और विचार विमर्श में भारत की भागीदारी के परिणामस्वरूप ही भारत संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का 1945 में प्रारंभिक सदस्य बन सका।

औपनिवेशिक शासनकाल के अंत में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया और नेहरू को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उनकी विदेश नीति के दृष्टिकोण अधिक तीव्र और स्पष्ट हो गए। नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को एक प्रसारण में उनकी आदर्शवादी दृष्टि के माध्यम से भारत की विदेश नीति के बुनियादी मार्गदर्शक के सिद्धांत को अपनाते की बात कही। नेहरू ने अपनी विदेश नीति को अपनाने में राष्ट्रीय हितों के बुनियादी तत्वों को उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दबाव वाले मुद्दों के साथ इस तरह से जोड़ने की कोशिश की, जिससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के मार्ग में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जातिवाद इत्यादि अनेक चुनौतियाँ थीं, जिनका अंत करके भारत शक्ति गुटों से गुटनिरपेक्षता और निरपेक्षता और एशिया और अफ्रीका के नए उभरते राष्ट्रों के बीच अधिक मित्रता और एकजुटता सब जुड़े हुए दिखने लगे। भारत ने विविधता में एकता के सिद्धांत को ग्रहण करते हुए अपने पड़ोसी

2 / NEERAJ : वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति

देशों खासकर चीन के साथ घनिष्ठ मित्रता की एकतरफा योजना विकसित करने की हद तक चला गया, किंतु चीन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए कभी भी भारत की आदर्श विदेश नीति को महत्त्व नहीं दिया। संक्षेप में नेहरू ने प्रारंभिक काल में आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति का निर्माण किया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विदेश नीति मूल्य

विश्व-दृष्टिकोण के निर्माण में भारत के सभ्यागत मूल्यों, इसके दर्शन, संस्कृति और पिछली कई शताब्दियों के इतिहास और विरासत का योगदान रहा है। आधुनिक समय में भारत की विदेश नीति के निर्माण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भारत की अपनी स्वतंत्रता को अफ्रीका और एशिया में अन्य सभी उपनिवेशित लोगों की स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा माना। भारत को अन्य सभी देशों के लिए औपनिवेशिक लोगों की स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरक बनना चाहिए।

भारत का मानना था कि जब तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर उपनिवेशवाद और नस्लवाद हावी रहेगा, तब तक भारत की अपनी स्वतंत्रता खतरे में रहेगी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लोकप्रिय आंदोलन था, जो अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी के मूल्यों पर आधारित था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष ने लोगों को विभिन्न जातियों, भाषाई समूहों और समुदायों को एक एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन में ला दिया था। 1905 के बंगाल विभाजन ने भारतीय जनता को बहुत आंदोलित किया था। कई महत्त्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को लोकप्रिय आंदोलन के रूप में देखा। महात्मा गाँधी ने अपने अफ्रीका के प्रवास के दौरान नस्लवाद और रंगभेद के काम को देखा था, इन सब परिस्थितियों में स्वतंत्रता आंदोलन से निकले मूल्य भारतीय विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए।

जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को भारत के विश्व दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए घोषणा की कि भारत की विदेश नीति का मुख्य मानदंड औपनिवेशिक और आश्रित देशों के लोगों की मुक्ति है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत की विदेश नीति में एक अन्य सिद्धांत यह रखा कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के साथ कभी भी अपने संबंधों को गंभीर नहीं करेगा। भारत जैसा एक नव स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन और अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों के साथ अपने संबंधों को समाप्त नहीं कर सकता, अपितु आर्थिक विकास के लिए उसे अन्य राष्ट्रमंडल के समर्थन की आवश्यकता थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के

विश्व दृष्टिकोण का विकास

ब्रिटिश शासन काल में राज्यतंत्र, न्यायिक प्रणाली, जनगणना प्रणाली, रेलवे, अखिल भारतीय सेवा, प्रशासनिक संरचना, डाक प्रणाली, कराधान प्रणाली, कपड़ा मिलों की स्थापना, कारखानों का निर्माण सभी का भारत पर एक एकीकृत प्रभाव पड़ा। इन परिवर्तनों ने भारत के लोगों में एक नवचेतना का जागरण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना का परिणाम

थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक सत्रों में विचार-विमर्श के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया। इसका एक उदाहरण महात्मा गाँधी है, जो 1919 में तुर्की में खिलाफत की बहाली के समर्थन में सामने आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गाँधी ने स्वराज के प्रस्ताव को खिलाफत की माँगों के साथ जोड़ते हुए दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए असहयोग की योजना अपनायी। इसी प्रकार 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन में हाकिम अजमल खान की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक प्रस्ताव रखने का फैसला किया था। 1938 के हरिपुर अधिवेशन में सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को विदेश नीति में शामिल करने का संकल्प किया। वर्तमान में भी ये दोनों सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधारशिला बने हुए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में जयपुर में आयोजित 55वें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि भारत विश्व शांति, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, नस्लीय समानता और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है।

नेहरू का काल

जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा विदेशमंत्री बने। उन्होंने देश की विदेश नीति की बारीकियों को सैद्धांतिक और संचालनात्मक रूप दिया। नेहरू एक आदर्शवादी विचारक थे, इसलिए उन्होंने जिस विदेश नीति की कल्पना की थी, वह देश के मूल राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के बजाय उनकी नैतिकतावादी विश्व दृष्टि के अनुरूप अधिक प्रतीत होती है। नेहरू ने स्वतंत्रता से पहले ही पश्चिम के हमलों के बीच एफ्रो-एशियाई एकजुटता के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें विश्व दो गुटों में विभाजित था, ऐसी स्थिति में, नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति विकसित करने के लिए स्पष्ट रूप से अन्य देशों, विशेषकर, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर काम किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्षता की विशेषताओं के साथ भारत की विदेश नीति का सैद्धांतिक आधार बन गया। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवेक रक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के गुणों और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के अलावा भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू भी बना।

भारत की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित थी। जिसका उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों की स्थापना करना था। भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, एक-दूसरे के प्रति गैर-आक्रामकता, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व आदि थे। नेहरू की पंचशील के सिद्धांतों में दृढ़ आस्था

थी। उनका मानना था कि भारत पड़ोसी देशों विशेषकर चीन के साथ व्यवहार में पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेगा।

नेहरूवादी सहमति

भारतीय विदेश नीति के विषय विशेषज्ञ भारत की विदेश नीति में नेहरूवादी सहमति की बात करते हैं। उनके अनुसार भारत की विदेश नीति 'नेहरूविथन सर्वसम्मति' उन आदर्शों और सिद्धांतों से बनी है, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय विकसित हुए थे; जैसे—नस्लवाद का विरोध, रंगभेद विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध आदि गाँधीवादी विश्व दृष्टिकोण से आये थे। नेहरू ने विदेश नीति के निर्माण में गाँधीवादी मूल्यों और आकांक्षाओं को आत्मसात किया था और उन्हें एक आधुनिक भारत के विचार के साथ जोड़ा था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर सभी विचारकों ने दो विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में लोकतंत्र, समाजवाद और फासीवाद के विचारों को निकटता से देखा। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को देखते हुए नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटनिरपेक्षता के मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया।

शीत युद्ध के दौरान विश्व की दो महाशक्तियों ने विकासशील देशों को दोनों में से एक पक्ष को चुनकर विकास करने पर बल दिया, वहीं नेहरूवादी नीति गुटनिरपेक्ष सत्ता की राजनीति, छद्म युद्ध, सैन्य गठबंधन और हथियारों की दौड़ की अस्वीकृति थी। नेहरूवादी नीति के बारे में विचारकों में मतभेद है। जहाँ कुछ विचारक नेहरू के गुट निरपेक्षतावाद को आदर्शवाद और खोखली नैतिकता के रूप में वर्णित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहरू को एक आदर्शवादी के रूप में वर्णित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहरू को एक आदर्शवादी के रूप में देखने के लिए विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है, जिन्होंने कुछ आदर्शों में भारतीय विदेश नीति को आधार बनाने की माँग की या एक यथार्थवादी के रूप में, शीत युद्ध और एक द्विध्रुवीय दुनिया के खतरे को दूर करने के लिए कूटनीति को अत्यधिक महत्त्व दिया। 1950 और 1960 के दशक में भारत की विदेश नीति का गुटनिरपेक्षता की ओर झुकाव अत्यधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी था।

1970 के दशक में शीत युद्ध में वृद्धि और परमाणु निर्माण ने पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के खतरे को जन्म दिया। 1970 के दशक में इंदिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, जो आदर्शवादी सिद्धांतों के बजाय व्यावहारिक और यथार्थवाद की अभ्यासी थी। उन्होंने भारत के मानसिक विश्व दृष्टिकोण को बदल दिया था। वे राजनीतिक निपुणता और राजनयिक और कुशाग्रता से प्रदर्शन में, भारतीय विदेश नीति के कारण पूरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक के समर्थन को सूचीबद्ध करने में सक्षम थी। इस प्रकार 70 के दशक के परिवर्तनों ने विदेश नीति पर 'नेहरूवादी सहमति' से पर्दा हटा दिया।

शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति

शीतयुद्ध के काल में भारत की विदेश नीति पाँच प्रधानमंत्रियों—लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और राजीव

गाँधी के समग्र मार्गदर्शन में संचालित की गई थी। नेहरू की मृत्यु के पश्चात शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके छोटे से शासनकाल के दौरान में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ। ऐसे समय में शास्त्री जी ने भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनुकरणीय साहस दिखाया, जिसके परिणामस्वरूप भारत की जीत हुई। ताशकंद में युद्ध के बाद की शांति वार्ता भी शास्त्री जी के नेतृत्वकाल में हुई थी।

तत्पश्चात इंदिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके नेतृत्व के काल में भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और पंचशील सहित 'नेहरूवादी सहमति' के साथ प्रमुख विराम देखे गए। इंदिरा गाँधी ने देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए भारत की विदेश नीति में बदलाव किया और उसे नेहरूवादी आदर्शवाद से दूर कर दिया। 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के माध्यम से उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ विश्व के अन्य देशों को यह संदेश दिया कि भारत को अब मात्र एक राष्ट्र के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गाँधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति पहली बार एक यथार्थवादी नीति के रूप में परिलक्षित हुई। इंदिरा गाँधी के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री का पद मोरारजी देसाई ने संभाला। अपने छोटे से शासनकाल के दौरान उनकी विदेश नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर नहीं रहा, वे भारत की गुटनिरपेक्षता को वास्तविक गुट निरपेक्षता में बदलना चाहते थे, हालांकि उन्होंने कभी भी 'वास्तविक' शब्द का वर्णन नहीं किया। इसी प्रकार 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत घुसपैठ के दौरान चरण सिंह सरकार किसी भी प्रकार का निर्णायक दृष्टिकोण अपनाने में विफल रही।

1984 में जब राजीव गाँधी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो भारतीय विदेश नीति कुछ आंशिक परिवर्तनों के लिए तैयार थी। राजीव गाँधी की नीति देश में चल रहे जातीय संघर्षों के समाधान को हल करने की थी, इसलिए अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने असम समझौता, मिजो समझौता एवं पंजाब में शांति की स्थापना के लिए 1985 का समझौता किया। इसी प्रकार शांति समझौतों में भारत में श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति सेना के नाम पर अपने एक सैन्य दल को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई, अपितु बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की जान चली गई। इस प्रकार राजीव गाँधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के लिए काफी चिंताजनक और हानिकारक रही।

1990 के दशक के दौरान भारत की विदेश नीति

1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनका भारत की विदेश नीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के विभाजन के साथ ही विश्व व्यवस्था का परिदृश्य बदल गया। विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था से एकध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया।

4 / NEERAJ : वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति

सोवियत संघ ने भारत को सुरक्षा कवच प्रदान किया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार पर अमेरिका ने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए भारी दबाव बनाया। नरसिम्हा के शासन काल के दौरान भारत की विदेश नीति निरंतर दबाव में रही। इसी काल के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1990 के दशक में सार्वभौमिक हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत के पास उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का पालन करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था।

नरसिम्हा राव के शासन काल में विदेश आर्थिक नीति के क्षेत्र में 'पूर्व की ओर देखो' की नीति की घोषणा कर बड़ा कदम उठाया। राव का कार्यकाल विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। पहली बार भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए दरवाजे खुले।

1990 के दशक का दूसरा भाग भारत में गठबंधन की सरकारों का रहा, जिसमें तीन प्रधानमंत्रियों का शासनकाल अस्थिर रहा। ऐसी स्थिति में विदेश नीति में प्रगति नहीं हुई। प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने अपने छोटे से शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति को नयी दिशा प्रदान की। गुजराल ने भारतीय विदेश नीति के दायरे में एक नया विचार पेश किया, जिसे गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के पाँच मूल सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को छोड़कर बाकी पड़ोसियों के लाभ का विस्तार था।

एनडीए के तहत भारत की विदेश नीति-1

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में सत्ता में आयी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ आंतरिक और बाहरी दृष्टि में कांग्रेस से काफी भिन्न थीं। वाजपेयी सरकार ने अपने शासनकाल की तीनों सरकारों के पहले दिन से ही जहाँ एकतरफ रूसी संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की बात की, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ घनिष्ठ सहयोग के पक्ष में भी थी। इसके अतिरिक्त वाजपेयी सरकार ने दक्षिण एशिया के देशों विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वाजपेयी के नेतृत्व काल में ही भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। परमाणु परीक्षण के उपरांत एनडीए ने दो पहलों को बढ़ावा दिया—परमाणु शक्ति को बढ़ावा देना और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखना। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के साथ स्वयं को परमाणु हथियार वाला राज्य घोषित कर दिया और तत्पश्चात एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में परमाणु ऊर्जा क्लब में शामिल होने की माँग की।

पोखरण-II के बाद भारत के खिलाफ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, लेकिन भारतीय राजनीतिक नेतृत्व और कूटनीति के

परिणामस्वरूप इन आलोचनाओं और प्रतिबंधों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम था। वाजपेयी सरकार ने अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए अमेरिका को बातचीत में शामिल किया। इसी के परिणामस्वरूप मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 (9/11) को हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका के साथ संबंधों ने एक नया रणनीतिक आयाम प्राप्त किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। बुश के प्रशासन काल में एशिया और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए भारत को एक रणनीतिक भागीदार के रूप में शामिल करना शुरू किया।

बुश प्रशासन काल के दौरान ही पोखरण-II के समय के कई प्रतिबंधों को हटा लिया गया। भारत-पाकिस्तान संबंधों को सुदृढ़ करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री वाजपेयी का मानना था कि "आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं।" इस भौगोलिक नियतिवाद को महसूस करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार करने के लक्ष्य से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर की बस यात्रा पर गए थे। कारगिल युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों को पुनः सुधारने के लिए 2001 में परवेज मुशरफ को आगरा आमंत्रित किया।

यूपीए के दौरान भारत की विदेश नीति

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दस वर्षों (2004-2014) में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भारतीय विदेश नीति का संरक्षक था। यूपीए (UPA) सरकार द्वारा भारत की विदेश नीति में लाए गए प्रमुख पुनर्रचनाओं में से एक भू-रणनीतिक से आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना था। यूपीए सरकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विदेश नीति को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की भी माँग की। आर्थिक विचारों के अतिरिक्त संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति ने देश को अलग-अलग शासनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधात्मक प्रौद्योगिकी व्यवस्थाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास किए।

यूपीए के शासनकाल में भारत-पाकिस्तान संबंधों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सितंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सत्र के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशरफ से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने कश्मीर सहित सभी समस्याओं की शांतिपूर्ण हल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए कई विश्वास बहाली उपायों पर दोनों देश सहमत हुए। 2006 में भी गुटनिरपेक्ष देशों के हवाना सम्मेलन ने दोनों देशों को एक शिखर बैठक करने का अवसर दिया। चीन के साथ भी अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। 2005 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने भारत की यात्रा की, जिसमें दोनों देशों ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।